सोनू @अमर

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1418/2013)

18 जुलाई, 2017

[एस. ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 120 बी, 364 ए, 302,328 ए और 201-अपहरण और हत्या-तथ्यों पर, पीड़ित का अपहरण और हत्या-धारा 120 बी, 364 ए, 302,328 ए और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ए1 से ए5 की सजा और आजीवन कारावास की सजा-धारा 328 और 201 के तहत ए6 की सजा और सात साल की सजा-पीडब्लू1 और पीडब्लू3 की गवाही के आधार पर, आरोपी के प्रकटीकरण बयान के अनुसार की गई बरामदगी और आरोपी के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर)-अपील पर उच्च न्यायालय ने कहाः अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी और बाद में की गई बरामदगी को प्रकटीकरण बयान के अनुसार साबित किया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 65बी (4) - व्याख्या - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता - कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की स्वीकार्यता - जब सीडीआर को ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया गया तो कोई आपत्ति नहीं ली गई - अस्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति की स्वीकार्यता इस स्तर पर - माना गया: सबूत के तरीके या विधि से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने के समय उठाई जानी चाहिए, बाद में नहीं - महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या दोष को चिह्नित करने के चरण में ठीक किया जा सकता था दस्तावेज़ - दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्तियाँ जो स्वयं अस्वीकार्य हैं, अपीलीय स्तर पर भी ली जा सकती हैं क्योंकि यह एक मौलिक मुद्दा है - सबूत का तरीका या तरीका प्रक्रियात्मक है और आपत्तियाँ, यदि परीक्षण में नहीं ली जाती हैं, तो अपीलीय स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है चरण - यह आपत्ति कि धारा 65 बी (4) में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण सीडीआर अविश्वसनीय हैं, को इस चरण में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आपत्ति सबूत के तरीके या विधि से संबंधित है, चंचल सिंह का मामला सामान्य नहीं बताता है कि अभियुक्त किसी आपराधिक मामले में दस्तावेज़ के सबूत के तरीके पर आपत्ति करने के अपने अधिकार को छोड़ने में सक्षम नहीं है।

धारा 65बी (4) - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साबित करने के लिए प्रमाण पत्र - माना गया: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री धारा 65बी में निहित

प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकती है - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि इसके साथ धारा 65बी (4) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र न हो।) - इस न्यायालय ने 2014 में, अनवर के मामले में माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रमाणन के बिना साक्ष्य में अस्वीकार्य है -इस न्यायालय ने 2005 में नवजोत संधू के मामले में माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इस क्षेत्र तक ही सीमित है। अनवर के मामले में खारिज कर दिया गया था - अनवर के मामले में, न्यायालय ने 'संभावित ओवररूलिंग' के सिद्धांत को लागू नहीं किया था - यदि अनवर के मामले में निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले लेनदेन अनियंत्रित हो जाएंगे और न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा - जैसा कि अनवर के मामले में हुआ था तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया था, न्यायिक औचित्य के मद्देनजर यह न्यायालय यह घोषित करने से बचता है कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा - मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है - 'संभावित अधिनिर्णय' का सिद्धांत - पूर्वव्यापी कार्रवाई - न्यायिक औचित्य.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 294 - अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा अदालत में दस्तावेज़ दाखिल करने की प्रक्रिया - दस्तावेज़ों को एक सूची में शामिल करना होगा और दूसरे पक्ष को प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा - यदि वास्तविकता नहीं है विवादित होने पर, ऐसे दस्तावेज़ को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार औपचारिक सबूत के बिना साक्ष्य में पढ़ा जाएगा।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उसके साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत एक प्रमाण पत्र संलग्न न हो। जहां तक इस स्तर पर अस्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति की स्वीकार्यता का संबंध है, जब सीडीआर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था, तब कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई आपत्ति उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय स्तर पर भी की गई थी। [पैरा 261 [168-बी-सी)

1.2 यह किसी का मामला नहीं है कि सी. डी. आर. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक रूप हैं, साक्ष्य में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। आपत्ति यह है कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष धारा 65 बी (4) द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किया गया था। यह स्पष्ट है कि प्रमाण के तरीके या विधि से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के

रूप में चिह्नित करते समय उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। इस परीक्षण को तत्काल मामले में लागू करते हुए, यदि सीडीआर को प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किए जाने पर आपत्ति जताई जाती, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को कमी को सुधारने का अवसर दे सकता था। यह भी स्पष्ट है कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियां जो स्वयं अस्वीकार्य हैं, अपीलीय स्तर पर भी ली जा सकती हैं। किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है, एक ऐसा मुद्दा है जिसे अपीलीय स्तर पर उठाया जा सकता है क्योंकि यह एक मौलिक मुद्दा है। सबूत का तरीका या तरीका प्रक्रियात्मक है और आपत्तियों को, यदि मुकदमे में नहीं लिया जाता है, तो अपीलीय स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि सबूत के तरीके पर आपत्तियों को किसी पक्ष द्वारा अपीलीय चरण में लेने की अनुमति दी जाती है, तो दूसरे पक्ष के पास कमियों को सुधारने का अवसर नहीं होता है। राज्य के वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयानों का उल्लेख किया। पी. सी. 1973 स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य की उक्त श्रेणी के तहत आने वाले दस्तावेजों के एक उदाहरण के रूप में। सी. डी. आर. दस्तावेजों की उक्त श्रेणी में नहीं आते हैं। एक आपत्ति कि धारा 65 बी (4) में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण सी. डी. आर. अविश्वसनीय हैं, इस स्तर पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपत्ति

सबूत के तरीके या विधि से संबंधित है। तत्काल मामले में, सीडीआर के प्रमाण के तरीके पर आपत्ति करने में स्पष्ट विफलता है। [पैरा 27,28] [170-बी-जी]

1.3 धारा 295 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 अभियोजन या अभियुक्त द्वारा न्यायालय में दस्तावेज़ दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। दस्तावेज़ों को एक सूची में शामिल करना होगा और दूसरे पक्ष को प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा। यदि वास्तविकता विवादित नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। [पैरा 301 [173-ई-एफ] ।

1.4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपराधिक जाँच आ अभियोजनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को धारा 65 बी में निहित प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है। धारा 65 बी (4) की व्याख्या करते हुए, अनवर के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रमाणन के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में अस्वीकार्य है जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। इस अदालत द्वारा धारा 65 बी (4) की व्याख्या को नवजोत संधू में एक फैसले द्वारा तब तक लागू रखा गया जब तक कि अनवर के मामले में इसे खारिज नहीं कर दिया गया। इस देश की सभी आपराधिक अदालतें इस अदालत द्वारा

व्याख्या किए गए कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। नवजोत संधू में धारा 65 बी की व्याख्या के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त अवधि के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षण किए गए हैं। प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनवर के मामले में इस न्यायालय के फैसले को तब तक पूर्वव्यापी होना चाहिए जब तक कि 'संभावित अतिनिर्णय' के न्यायिक उपकरण को लागू नहीं किया जाता है। हालाँकि, निर्णय का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग न्याय प्रशासन के हित में नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणन के साक्ष्य में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिए गए आपराधिक मामलों को अपीलीय स्तर पर जब भी अभियुक्त द्वारा आपत्तियां ली जाती हैं, तो उन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अंतिम हो चुके मामलों को फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा। [पैरा 31,32 [[173-जी-एच; 174-ए-डी]

1.5 इस न्यायालय ने अनवर के मामले में संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू नहीं किया। यदि अनवर के मामले में निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले लेनदेन में गड़बड़ी नहीं होगी और न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अनवर के मामले का निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा

किया गया था, औचित्य की मांग है कि यह न्यायालय यह घोषणा करने से बचें कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा। इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक उपयुक्त मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यह प्रश्न अभियुक्त के खिलाफ अन्य मुद्दों के निर्णय को देखते हुए तत्काल विवाद के निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं है। निचली अदालत की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। [पारस 35,36) [176-बी-डी]।

दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 158:1 एस. सी. आर. 280; अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर (2014) 10 एस. सी. सी. 473: (2014) 11 एस. सी. आर. 399; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600: [2005) 2 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 79; पैडमैन बनाम हनवांता ए. आई. आर. 1915 पी. सी. 1; आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेश्वरसवामी (2003) 8 सेक. 752: (20031 4 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 450; चैनचल सिंह बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 1; शेख फरीद बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983 सी. आर. एल. जे. 487; गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 83; पी. सी. पुरुषोत्तमा रेड्डी बनाम एस. पेरुमल (1972) 1 एस. सी. सी. 9: [1972) 2 एस. सी. आर. 646; आई. सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, (19671 2 एस. सी.

आर. 762; के. माधव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 6 एस. सी. सी. 537: (2014 (7 एस. सी. आर. 328-संदर्भित।

वीक्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 232 यू. एस. 383 (1914); वुल्फ बनाम कोलोराडो, 338 यू. एस. 25 (1949); मैप बनाम ओहियो 367 यू. एस. 643 (1961); लिंकलेटर बनाम वॉकर 381 यू. एस. 618 (1965); आर. बनाम एच. एम. प्रिज़न ब्रॉकहिल के गवर्नर, पूर्व पी. इवांस (नं. 2) (2000) 4 सभी ई. आर. 15-संदर्भित।

<u>मामला विधि संदर्भ</u>

[1977] 1 एससीआर 280	संदर्भित	पैरा14
[2014] 11 एससीआर 280	संदर्भित	पैरा23
[2005] 2 पूरक एससीआर 79	संदर्भित	पैरा23
एआईआर 1915 पीसी 1	संदर्भित	पैरा24
[2003] 4 पूरक एससीआर 450	संदर्भित	पैरा25
1983 सीआरएलजे 487	संदर्भित	पैरा25
एआईआर 1946 पीसी 1	संदर्भित	पैरा25
1983 सीआरएलजे 487	संदर्भित	पैरा25
एआईआर 1943 पीसी 83	संदर्भित	पैरा26
[1972] 2 एससीआर 646	संदर्भित	पैरा26

[1967] 2 एससीआर 762	संदर्भित	पैरा33
[2014] 7 एससीआर 348	संदर्भित	पैरा35

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 1418/2013

2010 के सीआरए नंबर 1066-डीबी में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2012 से

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 1416/2013

आपराधिक अपील संख्या 1652 और 1653 /2014.

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड., सुनील मल्होत्रा, संतोष श्रीवास्तव, सुश्री सुधा श्रीवास्तव, कुना! मल्होत्रा, सुश्री रीता पुरी, पी. एन. पुरी, पवन सी. शर्मा, डी. बी. गोस्वामी, दीपक थोकचोम, श्री लोकनाथ रथ, डॉ. सुशील बलवाड़ा, हरिकेश सिंह, सत्येंद्र कुमार, राम लाल रॉय, अपीलार्थी के वकील।

विवेक सूद, यू. के. उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, विनोद शर्मा, दिनेश चंदर यादव, ए. ए. जी., पवन रेले, डॉ. मोनिका गुसैन, डी. के. गर्ग, धनंजय गर्ग, विश्व पाल सिंह, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय एल नागेश्वर राव, जे द्वारा सुनाया गया।

I. उपरोक्त अपीलों में धर्मेंदर @बंटी के साथ अपीलकर्ताओं को रमेश जैन के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई। अभियुक्त धर्मेंद्र @बंटी ने इस अदालत के समक्ष अपील दायर नहीं की। आरोपी रामपाल को आई. पी. सी. की धारा 328 और 20 के तहत दोषी ठहराया गया और 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा भी उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी, जिस पर हमारे समक्ष हमला नहीं किया गया है।

2. दिनेश जैन (पीडब्लू-I) ने एस. एच. ओ., गनौर पुलिस स्टेशन (पीडब्लू 31) से 26.12.2005 पर दोपहर 01:30 पर एक शिकायत के साथ संपर्क किया कि उनके पिता लापता थे, जिसके आधार पर पीडब्लू 31 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. के अनुसार, दिनेश जैन शाम 7 बजे 'आई. डी. 1' पर राइस मिल से निकला और घर चला गया, जबकि उसके पिता वहाँ रुके हुए थे। क्योंकि उसके पिता रात को 10:00 पर भी घर नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल किया और पाया कि वह बंद है। वह चावल मिल में गया और राधे, चौकीदार के अपने पिता के ठिकाने के बारे में पूछताछ की और उसे बताया गया कि उसके पिता रात 9.30 बजे पंजीकरण संख्या डीएल-8-एसवाई-4510 वाली अपनी मोटर साइकिल पर चावल मिल से निकले।। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपने पिता की तलाश की, लेकिन उनका पता

नहीं चल सका। उसे आशंका थी कि उसके पिता का अपहरण किया गया होगा।

3. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, पीडब्लू 31 ने राइस मिल का दौरा करके और पूछताछ करके जाँच शुरू की। 28.12.2005 पर बाई क्रॉसिंग के पास एक गड्ढे से एक मोटर साइकिल बरामद की गई थी। जैसे ही वाहन की नंबर प्लेट धुंधली हो गई, पी. डब्ल्यू. 31 ने इंजन नंबर को सत्यापित किया, इसकी तुलना पंजीकरण प्रमाण पत्र से की ताकि यह पता चल सके कि जब्त की गई मोटर साइकिल रमेश जैन की थी।

4. तारीख 09.01.2006 को, दिनेश जैन (पीडब्लू 1) और अशोक जैन (पीडब्लू 3) ने पीडब्लू 31 को सूचित किया कि पीडब्लू 1 के मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया था जिसने खुद को बंटी के रूप में पहचाना और जो बिहारी बोली में बोल रहा था। उसने उन्हें सूचित किया कि रमेश जैन उसकी हिरासत में है और रुपये की फिरौती की मांग की। उनकी रिहाई के लिए 1 करोड़। उन्हें दिल्ली नेटवर्क वाला एक और मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी कहा गया था, जिस पर भविष्य में कॉल किए जाएंगे। जाँच अधिकारी (पीडब्लू31) ने मृतक रमेश जैन से संबंधित चावल मिल का 17.01.2006 पर दौरा किया और पीडब्लू1, पीडब्लू3 और धीर सिंह (पीडब्लू7) से मुलाकात की। उन्होंने चार धमकी भरे पत्र (Exh.P 1 से P4), एक चाबी वाली अंगूठी (Exh.P 9), एक चांदी की अंगूठी

जिसमें एक कीमती पत्थर (Exh.P 10) था और मृतक द्वारा 25.12.2005 पर पहनी गई शर्ट का एक टुकड़ा सौंपा, जब उसका अपहरण किया गया था (Exh.P11)। पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 ने जांच अधिकारी को सूचित किया कि बंटी ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे बाई क्रॉसिंग के पास चाबी की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, कपड़े का एक टुकड़ा और समाचार पत्र की कटिंग पाएँगे। उन्होंने बाई क्रॉसिंग से उक्त वस्तुओं को एकत्र किया।

5. जांच अधिकारी ने एस. आर. ओ. विशेष प्रकोष्ठ, रोहिणी, दिल्ली के साथ मिलकर इस सूचना के आधार पर कि आरोपी तिब्बती बाजार का दौरा करेगा, 20.01.2006 पर छापेमारी करने वाले तीन दलों का गठन किया। पवन (ए1), सुरेंद्र (ए2) और धर्मेंद्र उर्फ बंटी (ए3) को दोपहर 11:45 पर गिरफ्तार किया गया था जब वे एक मारुति कार में तिब्बती बाजार, दिल्ली गए थे। उनके पास से उनके मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की गई।

6. 22.01.2006 पर, अमर @सोनू (AS) और परवीन (A4) को गनौर चौक, GT रोड, गनौर में बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया गया। सोनू (एएस) के पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। परवीन @टीटू (ए4) को जाँच के दौरान एक खुलासा बयान का सामना करना पड़ा कि रमेश जैन का अपहरण कर लिया गया था और रुपये की मांग की गई थी।

उनकी रिहाई के लिए उनके परिवार के सदस्यों से 1 करोड़ रुपये कमाए गए थे। परवीन (ए4) ने कहा कि रमेश जैन की हत्या कर दी गई थी और उनके शव को गांव खीरी खुसनम के बाबा रुडे नाथ मंदिर में दफनाया गया था। अपने खुलासा बयान में, सुरेंद्र (ए2) ने आगे खुलासा किया कि डॉ. रामपाल ने रमेश जैन को बेहोश रखने के लिए इंजेक्शन लगाए। उन्होंने आगे खुलासा किया कि रमेश जैन की हत्या 29.12.2005 पर की गई थी और उनके शव को बाबा रुडे नाथ मंदिर में एक गड्ढे में दफनाया गया था। धर्मेंद्र @बंटी (ए3) और सुरेंद्र (ए2) को भी खुलासा करने वाले बयानों का सामना करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वे उस जगह की पहचान कर सकते हैं जहां रमेश जैन की हत्या की गई थी और उन्हें दफनाया गया था।

7. जाँच अधिकारी का नेतृत्व परवीन (ए4), धर्मेंद्र (ए3) और सुरेंद्र (ए2) ने 22.01.2006 पर गाँव खीरी खुसनम में बाबा रुडे नाथ मंदिर में किया। जिस कमरे में रमेश जैन को कैद किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी, उसे ए2 ने ए4 की ओर इंगित किया था। रमेश जैन के शव को ए2 और ए4 द्वारा पहचाने गए स्थान से निकाला गया था। पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू6 के साथ पीडब्लू11 जय चंद, एस. डी. एम. उस स्थान पर मौजूद थे जहाँ से रमेश जैन के शव को गड्ढे से निकाला गया था।

8. 24.01.2006 पर, परवीन (A4) द्वारा एक प्रकटीकरण बयान दिया गया था, जिसके अनुसार उन्होंने उस स्थान की पहचान की जहां मोटर साइकिल की चाबी की अंगूठी, धमकी भरे पत्र और मृतक रमेश जैन की एक अंगूठी गांव बाई के क्रॉसिंग पर एक साइन बोर्ड के पास रखी गई थी। उसने आगे खुलासा किया कि उसने रमेश जैन की एक और अंगूठी गाँव घसोली में अपने घर पर एक जगह पर छिपा दी जिसे वह केवल पहचान सकता है। परवीन पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने मृतक की सोने की अंगूठी को छुपाया जिसे पीडब्लू1 द्वारा पहचाना गया और ज्ञापन Exh.PT/5 के माध्यम से बरामद किया गया। धर्मेंद्र @बंटी (ए3) जेड पुलिस दल शास्त्री पार्क, दिल्ली में स्थित एक किराए के कमरे में गया जहाँ से मृतक रमेश जैन का मोबाइल नंबर 9896351091 का सिम कार्ड एक छिपी हुई जगह से बरामद किया गया था। एक प्रकटीकरण बयान के अनुसार, उन्होंने उस स्थान की भी पहचान की जहां मृतक के अपहरण के बाद उसकी मोटर साइकिल फेंकी गई थी। 30.01.2006 पर, सोनू @Amar को इस आशय का एक प्रकटीकरण बयान का सामना करना पड़ा कि उसने रमेश जैन का बटुआ और कुछ दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, डायरी, तीन बिजली के बिल, दो पानी के बिल और अपनी दुकान की सीट के नीचे अपनी तस्वीरें छिपाई थीं जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में थीं। उक्त दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा सोनू उर्फ अमर (ए. एस.) की दुकान से जब्त किए गए थे। मृतक रमेश जैन के

मोटर साइकिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र बेघा रोड, गनौर में स्थित घर में टेबल के एक दराज से बरामद किया गया था, जिस पर पवन (ए 1) ने कब्जा कर लिया था। सुरेंद्र (ए2) द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर बेघा रोड पर स्थित एक ही कमरे से दो जिंदा गोलियों के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद की गई।

9. डॉ. राम पाल (ए6) ने 01.02.2006 पर उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस. डी. जे. एम.), गनौर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें एक खुलासा बयान का सामना करना पड़ा, जिसके आधार पर मृतक को बेहोश रखने के लिए इंजेक्शन देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सिरिंज गांव खीरी खुसनम के बाबा रुडे नाथ मंदिर की छत से जब्त की गई थी। उनके खुलासा बयान के आधार पर उनके घर में एक खाट के नीचे से एक कुदाल भी बरामद किया गया था।

10. जाँच अधिकारी ने मोबाइल कंपनियों के नोडल अधिकारियों से अभियुक्तों से बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन, मृतक के मोबाइल फोन और दिनेश जैन (पीडब्लू 1) के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडी रुपये) एकत्र किए।

11. आरोपी मनीष (ए 7), जो सोनू (ए 5) का चचेरा भाई है, ने एस. डी. जे. एम., गनौर की अदालत में 12.04.2006 को आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर अपहरण में ए5 की सहायता करने का आरोप है। उन्हें

मुकदमे से बरी कर दिया गया था। न्यायालय जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी जिसे चुनौती नहीं दी गई है। अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 364 ए, 302,328 ए और 201 के साथ 120 बी के दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। इसके अलावा, ए2 पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था। सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 1 के फैसले में ए1 से ए5 को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ए6 को आई. पी. सी. की धारा 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया और सात साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। दिनेश जैन (पीडब्लू 1) ने दोषी अपीलार्थियों की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की। उन्होंने आरोपी मनीष (ए7) को बरी करने के फैसले को भी चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री की विस्तृत पुनः प्रशंसा के बाद सभी अपीलों को खारिज कर दिया। ए1, ए2, ए4 और ए5 ने अपनी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि के खिलाफ अपील दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

12. हमने अभिलेख पर पूरी सामग्री और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच की है। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 की गवाही, आरोपी के प्रकटीकरण बयानों के अनुसार की गई बरामदगी और आरोपी, मृतक और पीडब्लू 1 के मोबाइल

फोन के सीडीआर पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा किया कि अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया कि आरोपी उचित संदेह से परे दोषी हैं। ट्रायल कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी की संलिप्तता पर भी चर्चा की। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः सराहना की और निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए प्रकटीकरण बयानों, परिणामी बरामदगी और मोबाइल फोन के सी. डी. आर. पर भरोसा किया।

13. 25.12.2005 को रमेश जैन अपनी राइस मिल से 9:30 बजे निकले। उनके शव को 22/23.01.2006 की दरम्यानी रात को गाँव खीरी खुसनम में मंदिर परिसर से निकाला गया था। डॉ. पंकज जैन (पीडब्लूएल6) द्वारा 23.01.2006 पर शव परीक्षण किया गया था। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि अपघटन की प्रक्रिया चल रही थी। अधिकांश स्थानों पर त्वचा को छील दिया गया था। शव के गले में एक मफलर मौजूद था। दोनों कलाई और टखनों को कपड़े के टुकड़े से बांधा गया था। हाइड हड्डी टूटी हुई पाई गई। पीडब्लू 16 की राय में रमेश जैन की दम घुटने से मृत्यु हो गई। उनके अनुसार, मृत्यु का संभावित समय 23.01.2006 से 3/4 सप्ताह पहले था। उन्होंने यह भी कहा कि सर्दियों के दौरान अपघटन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। दिनेश जैन (पीडब्लू!) ने बयान दिया कि रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। मैं उनके पिता की रिहाई के लिए करोड़ रुपये लेता हूं, जो एक व्यक्ति से 06.01.2006 पर एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से किया गया था, जिसने खुद को बंटी के रूप में पहचाना और जो

बिहारी बोली में बोल रहा था। उन्होंने उन मोबाइल फोन नंबर 9896351091 के बारे में भी बताया, जिन पर उनके पिता का नंबर 08.01.2006 और 09.01.2006 था, जिन पर फिरौती की मांग की गई थी। उसने आगे अपनी दुकान के पते पर उसे मिले धमकी भरे पत्रों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी अपदस्थ कर दिया कि उन्होंने अपने अपहरण के दिन अपने पिता द्वारा पहनी गई कमीज का एक टुकड़ा, एक चांदी की अंगूठी और अपने पिता की मोटर साइकिल की एक चाबी की अंगूठी को 16.01.2006 पर प्राप्त कॉल में निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र किया था। जब उनके पिता का शव निकाला जा रहा था, तब वह वहां मौजूद थे और उन्होंने शव को बाहर निकालने का वीडियो बनाया। अशोक जैन (पीडब्लू3), जो मृतक रमेश जैन के भाई हैं, ने रमेश जैन की रिहाई के लिए फिरौती के भुगतान के लिए की गई मांगों के बारे में पीडब्लू के साक्ष्य की पुष्टि की।

14. तिब्बती बाजार, दिल्ली से ए1 से ए3 तक की गिरफ्तारी से 20.01.2006 पर 11:45 बजे अभियुक्त द्वारा दिए गए कई प्रकटीकरण बयान सामने आए, जिसके अनुसार प्रासंगिक सामग्री बरामद की गई। प्रत्येक अभियुक्त से की गई बरामदगी के विवरण पर बाद में चर्चा की जाएगी। ए2 द्वारा ए4 को दिए गए एक प्रकटीकरण बयान के अनुसार मृतक रमेश जैन का शव भी बरामद किया गया था। टेलीफोन कंपनियों के नोडल अधिकारियों से प्राप्त सीडीआर जो बिना किसी आपत्ति के अदालत

में प्रदर्शित किए गए थे, स्पष्ट रूप से सभी अभियुक्तों की संलिप्तता को साबित करते हैं। अभियुक्त को अपराध करने का दोषी ठहराने के लिए निचली अदालतों द्वारा 25.12.2005 से 20.01.2006 की अवधि के दौरान अभियुक्तों के बीच किए गए कॉल की संख्या की विस्तृत और गहन जांच की गई थी। हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों से भिन्न होने का कोई कारण नहीं देखते हैं। न ही हम नीचे दिए गए न्यायालयों के कारणों और निष्कर्षों में कोई विकृति देखते हैं। समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 158 में इस न्यायालय द्वारा संक्षेपित सिद्धांतों द्वारा निम्नानुसार सीमित है।

15. मान लीजिए, रमेश जैन के अपहरण या हत्या का कोई सीधा सबूत नहीं है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। कई मामलों में, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में पालन करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार हैंः

1. जिन परिस्थितियों से अपराध के निष्कर्ष को साबित करने की कोशिश की जाती है, उन्हें स्पष्ट रूप से या बारीकी से स्थापित किया जाना चाहिए।

2. परिस्थितियां निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली होनी चाहिए।

3. संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं।

4. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।

(देखिएः शांति देवी बनाम राजस्थान राज्य, (2012) 12 एस. सी. सी. 158 10); (यह भी देखिएः हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) एस. सी. आर. 1091 (पी1097) शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 153)।

16. उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम पाते हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियों से अभियुक्त के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकलेगाः

ए. मृतक 23.12.2005 से लापता था और उसका शव 23.01.2006 पर एक मंदिर के परिसर से खोदा गया था।

बी. मृतक की रिहाई के लिए फिरौती की मांग पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 की मौखिक गवाही से साबित होती है।

सी. ए2 से ए4 का प्रकटीकरण विवरण और मंदिर परिसर से शव की बरामदगी।

डी. अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान जिसके अनुसार मृतक के मोबाइल नंबर का सिम कार्ड, उसका व्यक्तिगत सामान वाला बटुआ आदि सहित उससे संबंधित कई वस्तुओं की बरामदगी हुई थी।

ई. मोबाइल की सीडीआर जो स्पष्ट रूप से 25.12.2005 से 20.01.2006 की अवधि के दौरान आरोपी की बातचीत के साथ-साथ मृतक के मोबाइल फोन से किए गए कॉल सहित पीडब्लू1 को किए गए कॉल को दर्शाती है।

एफ. चांदी की अंगूठी, मोटर साइकिल की चाबी की अंगूठी और मृतक द्वारा 25.12.2005 पर पहना गया कपड़े का एक टुकड़ा जिसे आरोपी द्वारा पीडब्लू1 को भेजा गया था।

17. हम अभियुक्त के लिए ए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करना उचित समझते हैं।

<u>ए1-पवन (आपराधिक अपील संख्या 1416/2013)</u>

18. मृतक की मोटर साइकिल संख्या DL-8-SY-4510 का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रकटीकरण विवरण Exh.PDD के अनुसार A1 से बरामद किया गया था। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गन्नौर के बाघा रोड स्थित उसके घर के कमरे में पड़ी टेबल की दराज से बरामद हुआ।

19. ए1 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री डी. बी. गोस्वामी ने कहा कि ए1 और ए4 भाई हैं। ए4 और ए2 परिवहन व्यवसाय में भागीदार थे। उन्होंने कहा कि ए1 को उनके गांव घसोली, जिला सोनीपत में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इसके समर्थन में डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य पर भरोसा किया। डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 5, जो घसोली गाँव के निवासी हैं, ने बयान दिया कि पुलिसकर्मी 20.01.2006 पर परवीन (ए4) की तलाश में सुबह लगभग 9 बजे गाँव गए थे। उन्होंने कहा कि ए1 पुलिस के साथ थाने गया। उन्होंने अपनी कार में यात्रा की और पुलिस सरकार में चली गई। जीप। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि ए1 को ए2 और ए3 के साथ <आई. डी. 1 पर 11:45 पी. एम. पर तिब्बती बाजार, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में दिल्ली के रोहिणी पुलिस स्टेशन की पुलिस भी शामिल थी, जिसके अनुसार ए1 को गिरफ्तार किया गया था। डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 5 की इच्छुक गवाही स्वीकृति के योग्य नहीं है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने ए1 के प्रकटीकरण बयान के अनुसार की गई गिरफ्तारी और बाद की बरामदगी को साबित कर दिया है। विद्वान

वकील ने प्रस्तुत किया कि ए1 द्वारा उनकी आवाज का नमूना लेने के लिए दायर आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और इसलिए उन्हें अपनी आवाज का नमूना नहीं देने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है। जब अभियोजन पक्ष ने अदालत का रुख किया तो ए1 ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, ए1 ने अपनी आवाज का नमूना लेने के लिए एक आवेदन दायर किया और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरा होने के बाद ए1 को फिर से दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए निचली अदालत ने उक्त आवेदन का निपटारा कर दिया। इसलिए, ए1 के विद्वान वकील का यह तर्क देना गलत है कि आवाज के नमूने देने के लिए उनके आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि ए 1 के मोबाइल फोन की सी. डी. आर. से पता चलता है कि वह केवल ए 2, ए 3 और ए 4 पर कॉल कर रहा था। उन्होंने इस आधार पर कॉल को सही ठहराने का प्रयास किया कि ए4 उनका भाई था और ए2 उनके भाई का साथी था। उसके और ए3 के बीच 28 कॉल के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है जो बिहार से है और जो पीडब्लू 1 से 1 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग कर रहा था। ।

<u>ए2-सुरेन्द्र (आपराधिक अपील संख्या 1652/2014)</u>

20. ए2 को तिब्बती बाजार, दिल्ली में ए1 और ए3 के साथ 20.01.2006 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके पास एक मोबाइल

फोन था जिसका उपयोग उसने 25.12.2005 से 20.01.2006 के बीच 1, ए3 और ए4 के साथ बातचीत करने के लिए किया था। ए2 से तीन एसटीडी बूथ रसीदें Exh.P41, पी42 और पी43 बरामद की गईं। इन रसीदों से पता चलता है कि ए5 सोनू के मोबाइल नंबर 9896001906 पर कॉल किए जा रहे हैं। वह झिंझाना गांव का निवासी था और एसटीडी बूथ से टेलीफोन नंबर 01398257974 पर किए गए कॉल झिंझाना से संबंधित थे। गिरफ्तारी के समय उसके पास से <ID1,000/- की राशि भी बरामद की गई थी। माना जाता है कि यह राशि उन्हें ए5 सोनू ने दी थी। उसके प्रकटीकरण बयान Exh.PCC A2 के अनुसार पुलिस दल को बेघा रोड, गनौर में उसके किराए के आवास पर ले जाया गया और दो जिंदा गोलियों के साथ एक देसी पिस्तौल. PW5 मोहन लाल की उपस्थिति में 325 बोर बरामद किए गए। उन्होंने गनौर में रमेश जैन के अपहरण की जगह और गांव खीरी खुसनम में बाबा रुडे नाथ मंदिर में शव को दफनाए जाने की जगह की भी पहचान की। ए2 के विद्वान वकील श्री राम लाल रॉय ने देशी पिस्तौल और गोलियों की बरामदगी पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 22.01.2006 पर बरामद शव एक पुजारी का है न कि रमेश जैन का। इस तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष द्वारा कोई नींव नहीं रखी गई है। यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि शव एक पुजारी का है। हमारा मानना है कि शव रमेश जैन का है, जिसकी पहचान उसके रिश्तेदारों ने की है। चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि

त्वचा को कई स्थानों पर छील दिया गया था लेकिन शरीर की विशेषताओं का आसानी से पता लगाया जा सकता था। पीडब्लू 16 ने यह भी कहा कि सर्दियों के महीनों में अपघटन धीमा होता है। हमने रमेश जैन की तस्वीर देखी है और इसकी तुलना बरामद शव की तस्वीर से की है। हम आश्वस्त हैं कि बरामद किया गया शव मृतक रमेश जैन का है।

ए4-परवीन @टीटू (आपराधिक अपील संख्या 1653/2014)

21. एसटीडी बूथ रसीद एक्स. एच. उत्तर प्रदेश के शामली गाँव के एसटीडी बूथ से 01398257974 नंबर पर कॉल किए गए पी44 को ए4 से उसकी गिरफ्तारी के समय 22.01.2006 पर बरामद किया गया था। रसीद के अनुसार, मोबाइल No.9896001906 पर कॉल किया गया था जो सोनू (A5) का है। उसके द्वारा दिए गए खुलासा बयान के अनुसार, उसने जी. टी. रोड पर गाँव बाई क्रॉसिंग पर उस जगह की पहचान की जहाँ उसने मोटर साइकिल की चाबी की अंगूठी, मृतक रमेश जैन की चांदी की अंगूठी और धमकी भरे पत्र रखे थे। मृतक की एक सोने की अंगूठी भी गांव घसोली में उसके आवासीय घर से बरामद की गई। उन्होंने एक खुलासा बयान भी दिया जिससे पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ मृतक को गलत तरीके से रखा गया था। मोबाइल नंबर 9812016269 वाला उसका सिम कार्ड उसके आवासीय घर से जब्त किया गया था। रिकॉर्ड पर यह बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ लगातार

संपर्क में था। उसका मोबाइल फोन और खुलासा बयान के अनुसार की गई बरामदगी स्पष्ट रूप से अपराध में उसकी संलिप्तता को साबित करेगी।

ए5-सोनू (आपराधिक अपील संख्या 1418/2013)

22. ए. 5 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह बहुत ही असंभव है कि ए5 को गनौर चौक, जी. टी. रोड, गनौर में एक बस स्टॉप पर गिरफ्तार किया गया था। उनके अनुसार, ए5 को उनके घर से 20.01.2006 पर 10:15 (30) बजे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने डी. डब्ल्यू. 5 और डी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य पर भरोसा किया। हमें इस निवेदन में कोई सार नहीं मिलता है कि ए5 को 20.01.2006 पर ही गिरफ्तार किया गया था क्योंकि डी. डब्ल्यू. 8 की गवाही से यह स्पष्ट है कि 20.01.2006 पर ए. एस. की जबरन गिरफ्तारी के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। ए5 द्वारा एक प्रकटीकरण बयान दिया गया था जिसे Exh.PBB के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसके अनुसार ए5 की दुकान से मृतक का बटुआ बरामद किया गया था। गनौर मंडी में उनकी दुकान की सीट के नीचे से एक लैमिनेटेड पैन कार्ड, मृतक की एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर, तीन बिजली के बिल, दो पानी के बिल और 'अनु पूर्वी' शीर्षक वाले जैन मंत्रों की एक छोटी डायरी बरामद की गई। गिरफ्तारी के समय ए2 सुरेंद्र और ए4 परवीन से बरामद एसटीडी बूथ रसीद से पता चलता है कि उन्होंने 29 और 30 दिसंबर, 2005 को ए5 से

संबंधित मोबाइल No.9896001906 पर कॉल किए थे। ए. एस. को पटना के एक एस. टी. डी. बूथ से 06.01.2006 पर कॉल भी आया। उनके द्वारा दिए गए एक प्रकटीकरण बयान के अनुसार एक इंडिका कार जिस पर नं. अपहरण में प्रयुक्त डीएल-3 सीडब्ल्यू-2447 को जब्त कर लिया गया। श्री लूथरा के अनुसार, ए 5 के प्रकटीकरण बयानों के अनुसार की गई वसूली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 22.01.2006 और 04.02.2006 के बीच A5 द्वारा दिए गए छह प्रकटीकरण बयानों का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी दुकान पर अपनी सीट के नीचे से बटुए की बरामदगी की असंभवता पर टिप्पणी की। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वसूली एक सार्वजनिक स्थान से होती है जो सभी के लिए सुलभ है और इसलिए की गई वसूली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम श्री लूथरा से असहमत हैं क्योंकि उनकी सीट के नीचे से बटुए की बरामदगी कुछ ऐसी है जो उनकी जानकारी में है, हालांकि अन्य लोगों की उनकी दुकान तक पहुंच हो सकती है।

23. श्री लूथरा ने तर्क दिया कि सी. डी. आर. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि वे इसकी उप-धारा (4) के अनुसार प्रमाणित नहीं थे। उन्होंने अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एस. सी. सी. 473 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसके द्वारा राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एस. सी. सी. 600

में इस न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया था। बी. नवजोत संधू (ऊपर) मामले में इस अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। यह हो सकता है कि धारा 65-बी की उप-धारा (4) में विवरण वाला प्रमाण पत्र तत्काल मामले में दायर नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, भले ही कानून प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसा साक्ष्य देने की अनुमति देता हो।"

अनवर के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

"22. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य पर सामान्य कानून उसी को प्रस्तुत करेगा। सामान्य विशेष गैर-अपमानजनक, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित धारा 59 और 65-ए पर ध्यान देना छोड़ दिया। धारा 63 और 65 का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है; यह पूरी तरह से धारा 65-ए और 65-बी द्वारा शासित है। उस हद तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर कानून का बयान, जैसा कि इस अदालत ने नवजोत संधू में कहा है, सही कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं करता है। इसे रद्द करने की आवश्यकता है और हम ऐसा करते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 65-बी के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप आदि के मामले में, दस्तावेज़ लेने के समय प्राप्त धारा 65-बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होगा, जिसके बिना, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है।

23. अपीलार्थी ने सीडी, एक्सट के संबंध में धारा 65-बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पी-4, पी-8, पी-9, पी-10, पी-12, पी-13, पी-15, पी-20 और पी-22। इसलिए, इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, गीतों, घोषणाओं और भाषणों का उपयोग करने वाली भ्रष्ट प्रथा के संबंध में स्थापित पूरा मामला जमीन पर गिर जाता है।

अनवर के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, श्री लूथरा ने कहा कि सी. डी. आर. पर विचार नहीं किया जा सकता है।

24. हरियाणा राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विवेक सूद ने कहा कि सीडीआर को बचाव पक्ष की ओर से बिना किसी आपत्ति के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलीय स्तर पर सी. डी. आर. की स्वीकार्यता के मुद्दे को उठाने के लिए अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पैडमैन बनाम हनवांता, ए. आई. आर. 1915 पी. सी. 1 पर भरोसा रखा जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियां ट्रायल कोर्ट में उठाई जानी चाहिए। श्री सूद ने तर्क दिया कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्तियों के दो वर्ग हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी यह है कि एक दस्तावेज साक्ष्य में स्वयं अस्वीकार्य है। दूसरा वह है जहाँ आपत्ति दस्तावेज़ के प्रमाण के तरीके या तरीके के बारे में है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभियुक्त की आपत्ति सबूत के तरीके या तरीके के बारे में है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि सीडीआर साक्ष्य में स्वयं अस्वीकार्य हैं।

25. राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का खंडन करते हुए, श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति दस्तावेज़ की अस्वीकार्यता से संबंधित है न कि सबूत के तरीके से। उन्होंने आग्रह किया कि सीडीआर प्रमाण पत्र के बिना स्वीकार्य नहीं हैं जो अनवर के मामले में इस अदालत के फैसले से स्पष्ट है। उन्होंने आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलिनिगु विश्वेश्वरसवामी, (2003) 8 एस. सी. सी. 752 के फैसले का उल्लेख किया, जिस पर अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया कि

स्वीकार्यता से संबंधित आपत्ति अपीलीय स्तर पर भी उठाई जा सकती है। श्री लूथरा ने यह भी तर्क दिया कि आपराधिक मामले में आवश्यक सबूत को आरोपी द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चैनचल सिंह बनाम राजा सम्राट, ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 1 में प्रिवी काउंसिल के एक फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"दीवानी मामले में, एक पक्ष अगर चाहे तो सबूत को माफ कर सकता है, लेकिन एक आपराधिक मामले में सख्त सबूत दिया जाना चाहिए कि गवाह सबूत देने में असमर्थ है।"

उन्होंने आगे शेख फरीद बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1983 सीआरएलजे 487 में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 294 सीआरपी.सी. जो इस नियम का अपवाद है कि सबूत के तरीके का तथ्यों पर कोई लागू नहीं होता है ।

26. यह कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत एक प्रमाण पत्र न हो। इस मामले में हमारे विचार के लिए जो सवाल आता है, वह इस स्तर पर अस्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति की अनुमति है। मान लीजिए, जब सी. डी. आर. को निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया तो कोई आपत्ति नहीं की गई। अभिलेखसँ ई

प्रतीत नहि होइत अछि जे एहन कोनो आपत्ति उच्च न्यायालयक समक्ष अपीलीय चरणमे सेहो लेल गेल छल। गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी, ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 83 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"जहां आपत्ति यह नहीं है कि दस्तावेज़ अपने आप में अस्वीकार्य है, बल्कि यह है कि सामने रखा गया सबूत का तरीका अनियमित या अपर्याप्त है, यह आवश्यक है कि दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने और रिकॉर्ड में स्वीकार करने से पहले आपत्ति को परीक्षण में लिया जाना चाहिए। एक पक्ष तब तक झूठ नहीं बोल सकता जब तक कि मामला अपील न्यायालय के समक्ष नहीं आता है और फिर पहली बार सबूत के तरीके की शिकायत नहीं करता है। "

आर. वी. ई. वेंकटचाया गौंडर में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"आम तौर पर साक्ष्य की स्वीकार्यता पर आपत्ति तब ली जानी चाहिए जब इसे प्रस्तुत किया जाता है और बाद में नहीं। साक्ष्य में दस्तावेजों की ग्राह्यता के बारे में आपत्तियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः (i) एक आपत्ति कि जिस दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है वह स्वयं साक्ष्य में अस्वीकार्य है; और (ii) जहां आपत्ति साक्ष्य में दस्तावेज़ की ग्राह्यता पर विवाद नहीं करती है, लेकिन सबूत के तरीके की ओर निर्देशित होती है जो इसे अनियमित या अपर्याप्त होने का

आरोप लगाती है। पहले मामले में, केवल इसलिए कि किसी दस्तावेज़ को 'एक प्रदर्शनी' के रूप में चिह्नित किया गया है, इसकी स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति को बाहर नहीं किया गया है और बाद के चरण में या अपील या संशोधन में भी उठाए जाने के लिए उपलब्ध है। बाद के मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले आपत्ति ली जानी चाहिए और एक बार दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार करने और एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के बाद, यह आपत्ति कि इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाया गया तरीका अनियमित है, दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी स्तर पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"बाद का प्रस्ताव निष्पक्ष खेल का नियम है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या एक आपत्ति, यदि उचित समय पर ली जाती है, तो पक्ष को दोष को ठीक करने के लिए सबूत देने और सबूत के ऐसे तरीके का सहारा लेने में सक्षम बनाता है जो नियमित होगा। आपत्ति करने में चूक घातक हो जाती है क्योंकि उसकी विफलता से आपत्ति करने का हकदार पक्ष साक्ष्य देने वाले पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विरोधी पक्ष सबूत के तरीके के बारे में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर, एक त्वरित आपत्ति दो कारणों से साक्ष्य देने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैः पहला, यह न्यायालय को अपने दिमाग को लागू करने और स्वीकार्यता के प्रश्न पर अपना निर्णय देने में सक्षम बनाता है और दूसरा, साक्ष्य देने वाले पक्ष के

खिलाफ जाने वाले सबूत के माध्यम से अदालत के निष्कर्ष की स्थिति में, सबूत के नियमित तरीके या तरीके की अनुमति देने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने का अवसर और इस तरह विरोधी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति को हटाने का अवसर, साक्ष्य का नेतृत्व करने वाले पक्ष के लिए उपलब्ध है। इस तरह की प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए उचित है। ऊपर उल्लिखित दो प्रकार की आपत्तियों में से, बाद के मामले में, शीघ्र और समय पर आपत्ति उठाने में विफलता एक दस्तावेज के औपचारिक प्रमाण पर जोर देने की आवश्यकता को माफ करने के बराबर है, वह दस्तावेज जिसे साक्ष्य में स्वीकार्य साबित करने की मांग की जाती है। पहले मामले में, सहमति उच्च न्यायालय में आपत्ति उठाने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। [जोर दिया गया]

पी. सी. पुरुषोत्तमा रेड्डी बनाम एस. पेरुमल, (1972) 1 एस. सी. सी. 9 में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए एक अन्य मामले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। पहले जिन मामलों का उल्लेख किया गया था वे दीवानी मामले हैं जबकि यह मामला मुकदमे के दौरान बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने से संबंधित है। इस न्यायालय ने इस तरह की आपत्ति को अपीलीय स्तर पर यह अभिनिर्धारित करते हुए लेने की अनुमति नहीं दी कि - उन रिपोर्टों को बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। इसलिए अब यह प्रतिवादी के लिए उनकी स्वीकार्यता पर आपत्ति करने के लिए खुला नहीं है।

27. यह किसी का मामला नहीं है कि सी. डी. आर. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक रूप हैं, साक्ष्य में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। आपत्ति यह है कि उन्हें धारा 65 बी (4) द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना विचारण न्यायालय के समक्ष चिह्नित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रमाण के तरीके या विधि से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करते समय उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में। महत्वपूर्ण परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करते हुए, यदि सीडीआर को प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किए जाने पर आपत्ति जताई जाती, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को कमी को सुधारने का अवसर दे सकता था। उपरोक्त निर्णयों से यह भी स्पष्ट है कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियां जो स्वयं अस्वीकार्य हैं, अपीलीय स्तर पर भी ली जा सकती हैं। किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है, एक ऐसा मुद्दा है जिसे अपीलीय स्तर पर उठाया जा सकता है क्योंकि यह एक मौलिक मुद्दा है। सबूत का तरीका या तरीका प्रक्रियात्मक है और आपत्तियों को, यदि मुकदमे में नहीं लिया जाता है, तो अपीलीय चरण में अनुमति नहीं दी जा सकती है. यदि किसी पक्ष द्वारा सबूत के तरीके पर आपत्तियों को अपीलीय चरण में लेने की अनुमति दी जाती है, तो दूसरे पक्ष के पास कमियों को सुधारने

का अवसर नहीं होता है। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयानों का उल्लेख किया। पी. सी. 1973 स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य की उक्त श्रेणी के तहत आने वाले दस्तावेजों के एक उदाहरण के रूप में। सीडीआर दस्तावेजों की उक्त श्रेणी में नहीं आते हैं। हम संतुष्ट हैं कि धारा 65 बी (4) में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण सी. डी. आर. के अविश्वसनीय होने पर इस स्तर पर आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपत्ति सबूत के तरीके या तरीके से संबंधित है।

28. एक अन्य बिंदु जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या अभियुक्त सबूत के तरीके के अपने अधिकार को माफ करने में सक्षम है। श्री लूथरा का निवेदन है कि इस तरह की छूट दीवानी मामलों में स्वीकार्य है न कि आपराधिक मामलों में। वह प्रस्ताव के समर्थन में चैनचल सिंह के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर निर्भर है। प्रिवी काउंसिल ने माना कि आरोपी अपने अधिकार को माफ करने में सक्षम नहीं था। चैनचल सिंह के मामले का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। उस मामले में, मुद्दा साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत था, और यह था कि क्या पहले की न्यायिक कार्यवाही में दर्ज साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है या नहीं। सवाल यह था कि क्या पहले की न्यायिक कार्यवाही में किसी गवाह द्वारा दिए गए बयानों को बाद की न्यायिक कार्यवाही में बताए गए सत्य या तथ्यों को साबित करने के लिए प्रासंगिक

माना जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की अनुमति देती है कि गवाह बाद की कार्यवाही में साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है। चैनचल सिंह के मामले में, अभियुक्त ने बाद की कार्यवाही में सबूतों को पढ़ने पर आपत्ति नहीं जताई थी। इस संदर्भ में, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि एक दीवानी मामले में, एक पक्ष सबूत माफ कर सकता है, लेकिन एक आपराधिक मामले में, सख्त सबूत दिया जाना चाहिए कि गवाह सबूत देने में असमर्थ है। इसके अलावा, न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि गवाह सबूत नहीं दे सकता है। चैनचल सिंह ने यह भी माना किः

"दीवानी मामले में एक पक्ष अगर चाहे तो सबूत को माफ कर सकता है, लेकिन एक आपराधिक मामले में सख्त सबूत दिया जाना चाहिए कि गवाह सबूत देने में असमर्थ है। "

गवाह, जिसने पहले गवाही दी थी, बाद की कार्यवाही में इस आधार पर पेश नहीं हुआ कि वह तपेदिक के कारण अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ था, जैसा कि प्रक्रिया सर्वर द्वारा अपदस्थ किया गया था। इस संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न कि वह साक्ष्य देने में असमर्थ था या नहीं, इस संदर्भ में साबित किया जाना चाहिए और इस तरह के तथ्य के प्रमाण में यह एक शर्त थी कि पहले की कार्यवाही में दिए गए बयानों को बाद की कार्यवाही में साबित

किया जा सकता है। इसलिए, चैनचल सिंह का मामला एक सामान्य प्रस्ताव नहीं देता है कि एक अभियुक्त आपराधिक मामले में सबूत के तरीके की आपत्ति को माफ नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, सी. डी. आर. के प्रमाण के तरीके पर आपत्ति करने में स्पष्ट विफलता है और इसलिए मामला आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर में परीक्षण द्वारा कवर किया गया है।

29. हम श्री लूथरा के इस निवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि शेख फरीद के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। शेख फरीद के मामले में यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

"6. दीवानी मामलों में सबूत के तरीके को उस व्यक्ति द्वारा माफ किया जा सकता है जिसके खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की जाती है। इसे स्वीकार करना या साक्ष्य में उनके निविदा पर आपत्ति उठाने में विफलता इस तरह की छूट के बराबर है। 1973 में वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियमन तक आपराधिक मामलों में अभियुक्त से ऐसी कोई छूट की अनुमति नहीं थी। अभियुक्त को मुकदमे में एक मूक दर्शक होना चाहिए था, क्योंकि जब तक संहिता की धारा 342 (वर्तमान धारा 313) के तहत अपना बयान दर्ज करने का अवसर नहीं आता, तब तक वह अपना मुंह खोलने के लिए बाध्य नहीं था। तब भी वह जवाब देने और उन

परिस्थितियों को समझाने के लिए बाध्य नहीं था जो उसके खिलाफ पेश होने के रूप में उसके सामने रखी गई थीं। चैन्चल सिंह बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 1 के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त अपने अधिकार और उन दस्तावेजों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के दायित्व को माफ करने में सक्षम नहीं था जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता था। नतीजतन, अभियोजन पक्ष को गवाहों से पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया गया, भले ही आरोपी उन तथ्यों को चुनौती देने में रुचि नहीं रखते थे जिन्हें साबित करने की मांग की गई थी। असुविधा और देरी से बचा जा सकता था। "

7. समय की इस परिहार्य बर्बादी को समाप्त करने और त्वरित सुनवाई में इस तरह की बाधा को दूर करने की सुविधा के लिए संहिता की धारा 295 पेश की गई है। अभियुक्त अब उक्त अधिकार को माफ करने और समय बचाने में सक्षम है। यह एक नया प्रावधान है जिसमें निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। इसके लिए अभियोजक या अभियुक्त से, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में शुरू में उस दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है जिस पर उसके खिलाफ भरोसा किया जाना चाहिए। उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने या कोई विवाद नहीं होने का संकेत देने पर, न्यायालय अपने औपचारिक प्रमाण को समाप्त करने के लिए

अधिकृत है। वास्तव में वास्तविकता के बारे में कोई विवाद नहीं होने के संकेत के बाद, दस्तावेजों के प्रमाण को पूरी तरह से खाली औपचारिकता में बदल दिया जाता है। इस धारा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से विधायी प्रक्रिया द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण को पूर्ववत करना है।

8. संहिता की पूर्ववर्ती धारा 293 में भी कुछ दस्तावेजों के प्रमाण दिए गए हैं। यह निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 510 के अनुरूप है। यह दस्तावेजों की उस श्रेणी को सूचीबद्ध करता है, जिसका प्रमाण तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि न्यायालय स्वयं इसे आवश्यक न समझे। धारा 295 औपचारिक साक्ष्य के वितरण को अभियुक्त या अभियोजक पर निर्भर करती है, उनके खिलाफ उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की वास्तविकता पर विवाद नहीं करती है। इस तरह का विचारित वितरण धारा 293 के तहत दस्तावेजों के किसी भी वर्ग या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है, जिसमें सामान्य रूप से प्रामाणिकता ज्ञान, अवलोकन या मौखिक साक्ष्य को केवल औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने वाले लेखक के कौशल की तुलना में शामिल यांत्रिक प्रक्रिया पर अधिक निर्भर करती है। न ही इसे दस्तावेज़ के सापेक्ष महत्व या उसके संभावित मूल्य पर निर्भर किया जाता है। दस्तावेज़ प्राथमिक या द्वितीयक या मूल या पुष्टिकारक होने के कारण संहिता की धारा 295 को आकर्षित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसकी वास्तविकता पर विवाद न करना इसके लिए एकमात्र परीक्षा है।

9. अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह एक दस्तावेज़ है। इस तरह के दस्तावेज़ का प्राथमिक प्रमाण स्वयं रिपोर्ट है। यह एक समकालीन रिकॉर्ड है, जो निर्धारित रूप में तैयार किया गया है, जिसे डॉक्टर ने मृत शरीर के पोस्टमार्टम के दौरान देखा है, जबकि मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है। यह प्रासंगिक होने के कारण, इसे प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। लेकिन उत्पादन इसके प्रमाण की दिशा में केवल एक कदम है। इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 से 71 के तहत प्रदान किए गए प्रमाण के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता की स्थापना पर ही साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। संहिता की धारा 295 (1) अभियुक्त को सबूत के इस तरीके को स्वीकार करने या उप-धारा (1) के तहत ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर इसकी वास्तविकता के बारे में कोई विवाद नहीं उठाने के लिए भी सक्षम बनाती है। उप-धारा (3) न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने की आवश्यकता के बिना इसे साक्ष्य में पढ़ने में सक्षम बनाती है। धारा 294 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे "दस्तावेजों" के दायरे से बाहर रखने को उचित ठहरा सके। इसके प्रमाण का तरीका भी किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह माफ किया जा सकता है।

30. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 295 अभियोजन या अभियुक्त द्वारा न्यायालय में दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। दस्तावेज़ों को एक सूची में शामिल करना होगा और दूसरे

पक्ष को प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा। यदि वास्तविकता विवादित नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। शेख फरीद के मामले में फैसला इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इसलिए यह प्रासंगिक नहीं है।

<u>ओवररूल का प्रभाव</u>

31. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपराधिक जांच और अभियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी में निहित प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है। धारा 65 बी (4) की व्याख्या करते हुए, अनवर के मामले में इस न्यायालय ने माना कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रमाणन के बिना साक्ष्य में अस्वीकार्य है जैसा कि उसमें दिया गया है। विपरीत दृष्टिकोण अपनाने वाले नवजोत संधू के मामले को खारिज कर दिया गया।

32. इस अदालत द्वारा धारा 65 बी (4) की व्याख्या को नवजोत संधू में एक फैसले द्वारा तब तक लागू रखा गया जब तक कि अनवर के मामले में इसे खारिज नहीं कर दिया गया। इस देश की सभी आपराधिक अदालतें इस अदालत द्वारा व्याख्या किए गए कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। नवजोत संधू में धारा 65 बी की व्याख्या के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की कोई

आवश्यकता नहीं थी। 04.08.2005 और 18.09.2014 के बीच की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षण किए गए हैं। प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनवर के मामले में इस न्यायालय के फैसले को तब तक पूर्वव्यापी होना चाहिए जब तक कि 'संभावित ओवररुलिंग' का न्यायिक उपकरण लागू नहीं किया जाता है। हालाँकि, निर्णय का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग न्याय प्रशासन के हित में नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणन के साक्ष्य में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर तय किए गए आपराधिक मामलों को अपीलीय स्तर पर जब भी अभियुक्त द्वारा आपत्तियां ली जाती हैं, तब उन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अंतिम हो चुके मामलों को फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा।

33. आई. सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, (1967) 2 एस. सी. आर. 762 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि कोई स्वीकार्य कारण नहीं है कि वह अपने द्वारा घोषित कानून के संचालन को भविष्य तक सीमित नहीं कर सकता है और उन लेनदेनों को बचा सकता है जो पहले के कानून के आधार पर किए गए थे। न्यायविदों जॉर्ज एफ. कैनफील्ड, रॉबर्ट हिल फ्रीमैन, जॉन हेनरी विगमोर और कार्डोजो द्वारा व्याख्या किए गए संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि जब बाद का निर्णय पहले वाले को बदल देता है, तो बाद वाला

निर्णय कानून नहीं बनाता है, बल्कि कानून के सही सिद्धांत की खोज करता है और परिणाम यह है कि यह आवश्यक रूप से संचालन में पूर्वव्यापी है। चूँकि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून है, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह न्यायालय अपने द्वारा पहले घोषित कानून के अधिक्रमण में कानून घोषित करते हुए भविष्य के लिए घोषित कानून के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और उन लेनदेनों को छोड़कर जो पहले के कानून के आधार पर प्रभावित हुए थे। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने गोलक नाथ मामले में निम्नलिखित प्रस्ताव रखेः

"(1) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 245,246 और 248 से प्राप्त होती है न कि उसके अनुच्छेद 368 से जो केवल प्रक्रिया से संबंधित है। संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है।

(2) संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर संशोधन 'कानून' है और इसलिए, यदि यह इसके भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है, तो यह अमान्य है।

(3) संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 और संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 मौलिक अधिकारों के दायरे को कम करते हैं। लेकिन इस अदालत के पहले के फैसलों के आधार पर वे वैध थे। "

संयुक्त राज्य अमेरिका में 'संभावित अतिनिर्णय' के सिद्धांत पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने अनुचित खोज और जब्ती द्वारा प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित निर्णयों का उल्लेख किया। सप्ताह बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 232 यू. एस. 383 (1914) में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुचित खोज और जब्ती द्वारा प्राप्त साक्ष्य को आपराधिक मुकदमों में बाहर रखा जाना चाहिए। 1949 में, वुल्फ बनाम कोलोराडो, 338 यू. एस. 25 (1949) में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सप्ताहों में निर्धारित बहिष्करण का नियम राज्य न्यायालयों में कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। वुल्फ में निर्णय मैप बनाम ओहियो, 367 यू. एस. 643 (1961) में सुनाया गया था। इसके बाद, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने लिंकलेटर बनाम वॉकर, 381 यू. एस. 618 (1965) में संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया क्योंकि यह राय थी कि यदि मैप को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है तो यह न्याय प्रशासन के हित और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करेगा।

34. आर. बनाम एच. एम. प्रिज़न ब्रॉकहिल के गवर्नर, एक्स पी. में पिछले लेन-देनों पर एक निर्णय के अधिक्रमण का प्रभाव इंग्लैंड में भी चर्चा का विषय रहा है। इवांस (नंबर 2), [2000] 4 ए. आई. आई. ई. आर. 15, लॉर्ड स्लिन संभावित शासन के सिद्धांत से निपटने के लिए निम्नानुसार देखा गयाः

"इस मामले में संभागीय न्यायालय का निर्णय न केवल निर्णय की तारीख में धारा का अर्थ क्या था, बल्कि हमेशा धारा का सही अर्थ क्या था, यह घोषित करने के पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करता है। अदालत ने अपने फैसले के प्रभाव को भविष्य तक सीमित करने की कोशिश नहीं की। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें यह वांछनीय होगा, और किसी भी तरह से अन्यायपूर्ण नहीं होगा, कि न्यायिक निर्णयों का प्रभाव संभावित या कुछ दावेदारों तक सीमित होना चाहिए। यूरोपीय न्याय न्यायालय ने, हालांकि सावधानीपूर्वक और कभी-कभी, अपने फैसले के प्रभाव को अपने समक्ष मामले में विशेष दावेदार और उन लोगों तक सीमित कर दिया है जिन्होंने अपने फैसले की तारीख से पहले कार्यवाही शुरू कर दी थी। जिन लोगों ने शायद वर्षों पहले किए गए कार्यों की वैधता को चुनौती देने की कोशिश नहीं की थी, वे केवल संभावित रूप से निर्णय पर भरोसा कर सकते थे। इस तरह के पाठ्यक्रम ने शायद लंबे समय से लेनदेन को अव्यवस्थित करने और प्रतिवादियों के साथ अन्याय करने से बचा लिया।" [जोर दिया गया]

35. इस न्यायालय ने अनवर के मामले में संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू नहीं किया। दुविधा यह है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। के. माधव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 6 एस. सी. सी. 537 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पूर्व निर्णय इसके पूर्वव्यापी संचालन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए संभावित होगा। यदि

अनवर के मामले में निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले लेनदेन में गड़बड़ी नहीं होगी और न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अनवर के मामले का फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, इसलिए औचित्य की मांग है कि हम यह घोषणा करने से बचें कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा। हम इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक उपयुक्त मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ते हैं। किसी भी स्थिति में, यह प्रश्न अभियुक्त के खिलाफ अन्य मुद्दों के निर्णय को देखते हुए वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं है।

36. उपरोक्त कारणों से, निचली अदालत की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

अपीले खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।